Limaye and Mr. Nath Pai, why it was not clubbed with the other Short Notice Question. I have got a copy of that. That relates to Islamabad. This question is about the labour situation. That was the difficulty about it.

Now, we adjourn for lunch and meet again at 2-25 P.M.

13.20 hrs.

The Lok Sabha Adjourned for Lunch till Twenty-five minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at twenty-seven minutes past Fourteen of the Clock.

[Mr. Speaker *in the Chair.*]

MATTER UNDER RULE 377—*Contd.*

Industrial Licencing Policy—*Contd.*

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, उद्योग मन्त्री द्वारा जिस नई लाइसैंसिंग नीति की घोषणा की गई है उसके बारे में मेरी कुछ आपत्तियां और आक्षेप है। इस तरह की आपत्तियां पहले भी हम लोग यहां पर उठा चुके हैं, लेकिन मन्त्री महोदय अपनी हरकतों से बाज नही आते, उनकी आदतें नही सुधरतीं, जब भी उन्हें नीति के बारे में कोई घोषणा करनी होती है...

एक माननीय सदस्य : यह क्या लेंग्वेज है ?

श्री मधु लिमये : मैंने किसी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। मैंने केवल यह कहा कि यह न तो अपनी आदतें बदलते हैं और न अपनी हरकतों से बाज आते हैं। इसमें क्या असंसदीय भाषा है ?

मैं कह रहा था कि जब कभी मन्त्री महोदय को नीतियों के सम्बन्ध में कोई घोषणा करनी हो ता उन्हें चाहिए कि वह इस सदन के सामने आकर सदन को विश्वास में लेकर नई नीतियों का ऐलान करें।

मन्त्री महोदय को याद होगा कि जब दत्त कमेटी की रिपोर्ट आई तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस पर सदन में बहस होगी और बहस में जो मुद्दे उपस्थित किये जायेंगे उन पर सरकार सोचेगी तथा बाद में नई नीति का ऐलान करेगी। लेकिन दत्त कमेटी की रिपोर्ट पर पिछले सत्र में बहस नहीं हो पाई। कम से कम इस सत्र के प्रारम्भ में उनको खुद इस बहस को रखवाना चाहिए था। लेकिन वह भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने इस सत्र के आरम्भ होने के दो एक दिन पहले नई नीति का ऐलान किया और उसके बाद उस नीति के विषय को स्पष्ट करने के लिए शायद पिछली 14 तारीख को, यानि 14 मार्च को उन्होंने एक वक्तव्य दिया। असल में इस सदन को कोई मौका नहीं मिल रहा है कि उद्योग मन्त्रालय की जो नीतियां हैं उनके बारे में वह अपनी राय व्यक्त करे।

यह बार-बार कहते हैं कि हम पूंजी का और आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण नहीं चाहते है, समाजवाद की ओर बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जिस मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को और नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था को पैदा किया है वह न घोड़ा है और न गधा है। वह क्या चीज है यह वही जानें।

एक माननीय सदस्य : खच्चर।

श्री मधु लिमये : खच्चर का भी उपयोग होता है, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं। नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था के कारण न केवल सत्ता का और पूंजी का केन्द्रीकरण हो रहा है बल्कि ऐसे उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया जाता है जो हमेशा सरकार का समर्थन करते है, सरकार को पैसा देते हैं, सरकार का दरबार करते हैं और सरकार की खुशामद करते हैं। क्या सदन को इस बात का पता नहीं है कि उन लोगों को

[श्री मधु लिमये]

नीतियों के कारण, जो सरकार की वित्तीय संस्थाएं है उनकी कर्जे सम्बन्धी नीतियों के कारण तीन वर्षों में—मोनोपोलीज कमिशन की रिपोर्ट को आये हुए तीन वर्ष हो गये—उन्होंने तीन बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा दिया और उनमें सबसे ज्यादा उन लोगों को बढ़ावा दिया जा हमेशा सरकार के समर्थक रहते हैं, जैसे मफतलाल परिवार। इस सदन में पिछली बार श्री मोरार जी देसाई इस बात को कह चुके हैं कि तीन वर्षों में मोनोपोलीज कमिशन के रिपोर्ट के आने के बाद मफतलाल परिवार की कम्पनियों ने अपनी परिसम्पत्ति अथवा असेट्स को हर साल 50 प्रतिशत के हिसाब से बढ़ाया है। इसका मतलब है कि हर दो साल पर वह अपनी परिसम्पत्ति का दुगना कर रहे हैं। और उद्योग मंत्रालय कहता है कि हम समाजवाद लाना चाहते हैं, सत्ता के केन्द्रीकरण को कम करना चाहते, पूंजी के केन्द्रीकरण को कम करना चाहते हैं। इसी प्रकार से बिड़ला परिवार की कम्पनियों ने तीन वर्षों के अन्दर अपनी परिसम्पत्ति को 50 प्रतिशत बढ़ाया है। इसका क्या मतलब हुआ? छः साल में बिड़ला परिवार अपनी परिसम्पत्ति को दुगना करेगा, सरकार की मेहरबानी और कृपा से।

इसलिए मन्त्री महोदय को यहां पर घोषणा करनी चाहिए कि नई नीति पर अमल तभी किया जायेगा जब दत्त कमेटी की रिपोर्ट पर बहस करने का सदन को मौका दिया जायेगा। सदन के विभिन्न दलों और सदस्यों की जो राय है उसका वह अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो उन्होंने अपना खच्चर बनाया है मिश्रित अर्थ-व्यवस्था और नियन्त्रित अर्थ-व्यवस्था का उसको खत्म करके समाजवाद के सही रास्ते पर चलेंगे। मै जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए मंत्री जी तैयार हैं?

SHRI HEM BARUA (Mangaldai): On a point of order. This particular issue raises two vital points. One is that the hon. Minister has by passed Parliament when it is sitting. Another is that he made a statement relaxing his policy just on the eve of the FICCI conference.

MR. SPEAKER: That was why I allowed this.

SHRI HEM BARUA: I want the hon. Minister to clarify these vital points which arise out of this, because this would lead to the concentration of capital in the hands of a few, and the impression in the country is this that the hon. Minister was pressurised by some people, some industrialists and some businessmen to make these concession.

MR. SPEAKER: I allowed it only because of that.

श्री राम किशन गुप्त (हिसार): इसीलिये वनस्पति की कीमत बढ़ गई है।

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh): My point of order is this. I would like to know whether Government can take these *ad hoc* decisions by making announcements on various occasions just on the eve of the session. This is not the only occasion when such a thing has happened, because Shri Khadilkar has made similar disclosures about the insurance premia when Parliament was just going to meet. This is a bad habit developing among them, and this amounts to by passing the spirit of democracy. I would request that you may issue a directive to hon. Ministers not to make such announcements as they like outside the House.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): I also feel that by making these announcements outside the House, this House is being treated very shabbily by the hon. Ministers. After all, we are all elected Members of Parliament, and the hon. Minister should announce any major decision which he wants to take, on the floor of the House; otherwise, it would mean treating this House with contempt.

My second point is that there should be a discussion on the Dutt Committee's report on the accumulated monopolistic wealth

of all concerns, because we know that even after an inquiry was instituted, a licence has been granted to the Birla House. It is something extraordinary. I hope we shall be given an opportunity to discuss this. I also hope that you would issue a directive to the hon. Ministers not to do this kind of thing in the future.

SHRI S. R. DAMANI (Sholapur): I would like to submit that nothing of importance has been announced by the hon. Minister outside the House. Certain clarifications were required, and the hon. Minister had just given those clarifications outside the House. It cannot be said that even clarifications cannot be given outside the House. So, the point of order which has been raised is not relevant.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : हाउस के बाहर इस तरह की एनाउंसमेंट्स नहीं की जानी चाहियें। हाउस में की जानी चाहिए। हाउस सुप्रीम आथोरिटी है। इसमें इस तरह से चीज को छिपाया नहीं जाना चाहिये। इस तरह से छिपाना बड़ी शर्म की बात है। मोदी को इसमें फायदा पहुँचाया गया है। अपने दोस्तों को आप फायदा पहुँचाते हैं। डालडा के दाम बढ़ा दिये हैं, आपने। फिर आप समाजवाद का नारा लगाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप इस माइनोरिटी गवर्नमेंट को सावधान करें। आप हमारे हकों के कस्टोडियन हैं। आपको गवर्नमेंट को सावधान करने का हक है। ठीक तरह से वे गवर्नमेंट को चलायें। माइनोरिटी गवर्नमेंट को जरा शर्म आनी चाहिए।

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : दत्त कमेटी की रिपोर्ट पर बहस नहीं हुई। ऐसा करके सदन को नजर अंदाज किया गया है। यह बात साफ है। मैं आपका ध्यान एक दूसरी तरफ दिलाना चाहता हूं। इस सत्र के शुरू होने से पहले ही मैंने इस नीति के मुताल्लिक बिड़ला को गोआ में जो लाइसेंस दिया गया है, उसके बारे में एक मोशन दिया था। मैं देख रहा हूं कि सरकार की इस हाउस को नजर अंदाज नहीं कर रही है आप भी शायद नजर अंदाज कर रहे हैं। यदि उसकी इजाजत मिल गई होती और बिड़ला को गोआ में जो लाइसेंस दिया गया है, उसके मुताल्लिक बहस हो गई होती तो बहुत कुछ सफाई हो गई होती। तब यह भी हो जाता कि सदन को नजर अंदाज नहीं किया जा रहा है। उधर से ही नहीं, मैं देख रहा हूं कि आपकी तरफ से भी कुछ वैसा ही हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : उनके साथ-साथ आपने मुझे भी रोप इन कर लिया।

श्री अब्दुल गनी डार (गुड़गांव) : मैं समझता हूं कि लिमये जी, बनर्जी साहब, झा साहब को वक्त इस तरह से नहीं आपको देना चाहिए। इससे गवर्नमेंट मुश्किल में पड़ जाती है। यह माइनोरिटी गवर्नमेंट है। बम्बई में करोड़ों रुपये का रोजाना घालामाला होता है। इनको चन्दे कैसे मिलेंगे और कैसे यह गवर्नमेंट चल सकेगी ?

[شری عبدالغنی ڈار - میں سمجھتا ہوں کہ لمے جی - بنرجی صاحب - جھا صاحب کو وقت اس طرح سے نہیں آپ کو دینا چاہیئے - اس سے گورنمنٹ مشکل میں پڑجاتی ہے - یہ مائنورٹی گورنمنٹ ہے - بمبئی میں کروڑوں روپے کا روزانہ گھالا مالا ہوتا ہے - ان کو چندے کیسے ملیں گے اور کیسے یہ گورنمنٹ چل سکے گی -]

MR. SPEAKER : This is no point of order.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): Two objections have been raised by the hon. Member. The first objection concerns the question whether the policy which we have enunciated ought to have been announced in the House after consulting the House. Shri Madhu Limaye has said that there was no justification for Government to enunciate that policy two or three days before the House met for this session.

SHRI MADHU LIMAYE : Less than two days

SHRI F. A. AHMED: The other objection which has been raised is that while the House is sitting, some other policy has been enunciated without placing the matter before the House.

Incidentally, he has also raised the question that the House has not been provided with an opportunity of discussing the matter relating to the recommendation made by the Dutt Committee.

I would take the third point first and point out that so far as we are concerned, we have laid on the Table the Dutt Committee Report. It was naturally left to the House to discuss it.

श्री मधु लिमये : दत्त कमेटी पर बहस करवाने का वादा किया था। उसके पहले ही आपने यह किया :

SHRI SHRI CHAND GOYAL: We have moved in the matter; motions are pending.

SHRI F. A. AHMED: We would have no objection in discussing the matter.

श्री मधु लिमये : सरकारी कामकाज में क्या आपने उसको शुमार किया है? हमारे पास जो सरकारी कामकाज का ब्यौरा आया है, उसमें नहीं है।

SHRI F. A. AHMED: Any member could have given notice of a motion.

SHRI MADHU LIMAYE: We have. आप पढ़ते नहीं हैं बुलेटीन्ज को। नोटिस दिया गया है।

श्री रवि राय (पुरी) : 184 में नोटिस दिया गया है।

SHRI F. A. AHMED: So far as Government are concerned, we feel that this matter ought to have been discussed in the House before we took a decision. But we could not indefinitely for it to be discussed here. Therefore we had to take into consideration the recommendations made by the Planning Commission, the ARC and also the Dutt Committee and have consulted other bodies generally then we took certain decisions regarding those matters. As soon as the House met, we laid the published Notifications also on the Table. I have no objection to a discussion. Any day it can be discussed. If any Notifications are called for, after considering the views of the House, we can certainly modify any of the decisions and principles enunciated in that policy. I have no objection to the matter being discussed if the House so desires.

As for the point that Government ought not to have published the notification two or three days before the House met in so far as the policy was concerned, I submit Government have taken these decisions on the basis of material which was before them. It is for the House to consider the decisions taken by Government and make suggestions, and we will give our utmost considerations to them.

So for as the notification issued on 13 March is concerned, it is not a notification which enunciates any policy; it is a clarification of the policy enunciated which was notified on 18th February. Therefore, it is not necessary for us to place that matter before the House.

श्री मधु लिमये : एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा है कि इनकी नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था की जो नीति थी या सरकारी वित्तीय संस्थाओं की जो नीति थी उसकी वजह ऐसे परिवारों की कम्पनियों को बढ़ावा मिला है जो हमेशा सरकार का साथ देती है। मैंने मफतलाल और बिड़ला परिवार की कम्पनियों की बात की। क्या आप इन तथ्यों को काट सकते हैं? अगर नहीं तो इस केन्द्रीयकरण को कम करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

SHRI F. A. AHMED: This question goes into the merits of the policy which has been enunciated. May I tell the hon. member that so far as the new policy enunciated is concerned, it looks after the question whether some restrictions should be placed in the way of the monopolies? As the hon. member knows, we have laid down a policy that for an investment of upto one crore and involving foreign exchange of 10 per cent or Rs. 10 lakhs,

no licence is necessary except for the 20 larger houses.

श्री मधु लिमये : आप लाइसेंस देते रहते हैं।

SHRI F. A. AHMED : Similarly it is for the first time that we have given statutory protection to small scale industries; we have increased some items and are also considering whether further item cannot be added to them so that statutory protection is given for the development of small scale industry.

Then, also, for investment between Rs. 1 and Rs. 5 crores we have said that larger houses will not be generally allowed to enter in that category. Only in respect of investment above Rs. 5 crores for heavy investment or under the core sector, we will consider the application of the larger houses on the basis of priority with regard to industries which will be required in our country and there they will be allowed to file applications and the matters will be taken into consideration.

श्री शिव चन्द्र झा : क्या यह इंडस्ट्रियल पालिसी रेजोल्यूशन के खिलाफ नहीं है? उसको सैबोटेज किया जा रहा है।

MR. SPEAKER : The question before us was about the statement on major policies. The healthy convention that has been followed and that should be followed here is that on all new or major policies, immediately after the meeting of the House, if that is possible, the matter should come before the House, but in this case the position taken by the Minister is that the notification was in the nature of a clarification of a policy already enunciated.

SHRI MADHU LIMAYE : Thirty six hours before the House to meet.

MR. SPEAKER : Even if it is so, the practice is that immediately following that the Minister makes a statement in this House also, and that we discuss it at the earliest moment.

14.46 hrs.

Demands for Grants on Account 1970-71—*Contd.*

MR. SPEAKER : About the other matter, vote on account, I discussed it yesterday with the Minister and the many issues that were raised by way of points of order. The Minister informed me about the whole position, but I want that the House should also be informed of it, before I give my ruling.

SHRI NATH PAI (Rajapur) : The next time he comes to see you in your chamber, please send for us, so that we can assist you.

MR. SPEAKER : You assisted me in this House very well.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : Yesterday after the general debate on the Budget was over and before the Demands for Grants on Account were put before the House, certain points were raised regarding the provision of Rs. 175 crores for special assistance to the States. I had tried to explain that this provision was by way of loans and advances and that it did not involve the concept of a new service. I find that there is still some misunderstanding on this point, and therefore I want to make it clear that the entire assistance to the States under this provision of Rs. 175 crores will be given by way of recoverable loans. The word "assistance" was used only in the general sense and in accordance with the established usage. For instance, even loans given for plan schemes and other purposes have been referred to as assistance in the Notes on Demands for Grants.

The question was also raised whether these special loans to the States will be given in accordance with certain general principles which would be applied equally to all States. I wish to make it clear that this, in fact, is the case. As the Prime Minister mentioned in her reply to the general debate, the purpose of this provision is to enable the State Governments to take up worthwhile plan programmes in all those cases where, despite their very best efforts and after taking into account all plan assistance and the devolution of resources as recommended by the Finance Commission, the States concerned still have gaps in their resources.